

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : अशोक शिवहरे
सदस्य

पुनर्विलोकन प्र० क्र० ४७७-तीन/२०१४ विरुद्ध आदेश दिनांक
०३-०३-१४ पारित राजस्व मण्डल, म०प्र०, ग्वालियर प्रकरण क्रमांक
३६६४-तीन/२०१३.

राजेन्द्र प्रसाद शुक्ला पुत्र गोविन्द प्रसाद
नि० ग्राम बदरॉव तिवारियान, तह० सिरमौर,
जिला रीवा, म०प्र०

----- आवेदक

विरुद्ध

रामकुमार पुत्र सियाशरण ब्राह्मण,
निवासी ग्राम बरा कोठार, तह० हुजूर,
जिला रीवा म०प्र०

--- अनावेदक

श्री के०के० द्विवेदी, अभिभाषक - आवेदक
श्री मुकेश भार्गव, अभिभाषक--- अनावेदक

आदेश

(आज दिनांक २३.६.२०१४ को पारित)

यह पुनर्विलोकन का आवेदनपत्र मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, १९५९ (जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा ५१ के अन्तर्गत राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर के निगरानी प्रकरण क्र० ३६६४-तीन/२०१३ में पारित आदेश दिनांक ०३-०३-१४ से असन्तुष्ट होकर प्रस्तुत किया गया है।



2/ प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि अनावेदक रामकुमार द्वारा तहसील न्यायालय में पुनर्विलोकन आवेदन प्रस्तुत करने पर तहसीलदार ने अपने अन्तरिम आदेश दिनांक 28-9-13 द्वारा पुनर्विलोकन की अनुमति हेतु प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया और अनुविभागीय अधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 30-9-13 पुनर्विलोकन की अनुमति प्रदान की गयी। तहसीलदार के अन्तरिम आदेश दिनांक 28-9-13 के विरुद्ध आवेदक द्वारा निगरानी राजस्व मण्डल में प्रस्तुत की गयी जिसे राजस्व मण्डल ने अपने आदेश दिनांक 03-03-14 द्वारा खारिज किया है। अतः आवेदक द्वारा यह पुनर्विलोकन आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

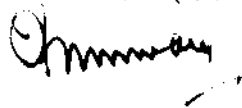
3/ मैंने उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर गम्भीरतापूर्वक विचार किया तथा उपलब्ध के अभिलेख का अवलोकन किया। आवेदक के अभिभाषक का तर्क है कि तहसीलदार का नामान्तरण आदेश अंतिम प्रकृति का था, इस कारण उसके विरुद्ध केवल अपील प्रस्तुत की जा सकती थी, पुनर्विलोकन प्रचलन योग्य नहीं था। उनका तर्क है कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पुनर्विलोकन अनुमति देने के पूर्व आवेदक को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया। इस संबंध में उन्होंने 2000 रा.नि. पृष्ठ 76 का न्यायदृष्टान्त प्रस्तुत कर तर्क प्रस्तुत किया कि पुनर्विलोकन की अनुमति बिना दूसरे पक्ष को सूचना एवं सूनवाई का अवसर दिये बिना नहीं दी जा सकती। इस वैधानिक तथ्य पर राजस्व मण्डल द्वारा आदेश पारित करते समय विचार नहीं किया गया जो अभिलेख से स्पष्टदर्शी त्रुटि है। उनका यह भी तर्क है कि पुनर्विलोकन का कोई आधार नहीं होते हुए भी अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पुनर्विलोकन की अनुमति प्रदान की है जो स्पष्टतः त्रुटिपूर्ण है। पुनर्विलोकन की अनुमति हेतु जो आवेदन दिया गया है उसमें परिसीमा अधिनियम की धारा 5 का आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया। अन्त में उनका तर्क है कि व्यवहार न्यायालय में स्वत्व का प्रश्न विचाराधीन है, इसलिये



व्यवहार न्यायालय के निर्णय तक राजस्व न्यायालय की कार्यवाही स्थगित रखी जाना चाहिये थी। अतः उन्होंने पुनर्विलोकन स्वीकार करने का अनुरोध किया है।

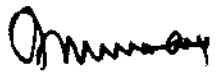
4/ अनावेदक के अभिभाषक का यह तर्क है कि अनावेदक ने भूमि सर्वे क्रमांक 172 का रकबा 0.149 हे. का ही विक्रय किया गया और शेष रकबा 0.462 हे. अपने पास रखा, किन्तु सम्पूर्ण रकबे पर नामान्तरण किस आधार पर दर्ज हुआ, इस तथ्य की जाँच के लिये तहसीलदार द्वारा अनुविभागीय अधिकारी से पुनर्विलोकन की अनुमति ली गयी है। आवेदक द्वारा निगरानी में तथा पुनर्विलोकन आवेदन में ऐसा कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे प्रश्नाधीन सम्पूर्ण रकबे पर उसके नामान्तरण को विधि अनुकूल होना माना जा सके। उनका तर्क है कि अपील योग्य आदेश के विरुद्ध पुनर्विलोकन ग्राह्य योग्य नहीं है, ऐसा कोई प्रावधान संहिता में नहीं है। अतः उन्होंने पुनर्विलोकन निरस्त करने का अनुरोध किया।

5/ राजस्व मण्डल ने अपने आदेश दिनांक 03-03-14 में यह निष्कर्ष निकाला है कि अनावेदक के नाम की भूमि सर्वे क्रमांक 172 के शेष रकबा 0.462 हे. पर आवेदक का नाम शासकीय अभिलेख में दर्ज होने का तथ्य परिलक्षित हुआ, जो जाँच का विषय होकर पुनर्विलोकन के लिये पर्याप्त आधार है। आवेदक को तहसील न्यायालय में जाँच कार्यवाही के दौरान अपना पक्ष रखने का उपचार प्राप्त है। जहाँ तक विचाराधीन भूमि पर व्यवहार वाद प्रचलित होने का संबन्ध है, व्यवहार न्यायालय से जो भी आदेश होंगे, राजस्व न्यायालय पर बन्धनकारी हैं। इससे स्पष्ट है कि निगरानी में जिन बिन्दुओं पर निष्कर्ष निकाले गये हैं, वही पुनर्विलोकन में आवेदक द्वारा प्रस्तुत किये गये हैं। पुनर्विलोकन आवेदन के आधार पर निगरानी में निकाले गये निष्कर्षों पर पुनर्विचार नहीं किया जा सकता। अपील योग्य आदेश के विरुद्ध पुनर्विलोकन आवेदन ग्राह्य नहीं किया जायेगा ऐसा कोई प्रावधान संहिता में नहीं है।



आवेदक द्वारा निगरानी में अथवा पुनर्विलोकन में ऐसा कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे प्रश्नाधीन भूमि सर्वे क0 172 के शेष रकबा 0.462 हे. पर उसके नामान्तरण को प्रथमदृष्टया सही होना माना जा सके। संहिता की धारा 109/110 के अन्तर्गत नामान्तरण स्वत्व के संबंध में संक्षिप्त जाँच के पश्चात स्वत्व के विधिवत अन्तरण होने पर ही किया जा सकता है। इस प्रकरण में प्रश्नाधीन भूमि सर्वे क0 172 के शेष रकबा 0.462 हे. पर नामान्तरण शासकीय अभिलेख में दर्ज होने का तथ्य परिलक्षित होने पर तहसीलदार द्वारा पुनर्विलोकन की अनुमति चाही गयी है जिसे प्रदान करने में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा कोई गलती नहीं की है। आवेदक को तहसील न्यायालय के समक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत करने का समुचित अवसर उपलब्ध है व निगरानी एवं पुनर्विलोकन में भी आवेदक को सुनवायी का अवसर प्रदान किया जा चुका है, इस कारण आवेदक द्वारा प्रस्तुत न्याय दृष्टान्त के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी के पुनर्विलोकन अनुमति आदेश में हरतक्षेप करना विधिसंगत प्रतीत नहीं होता।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर पुनर्विलोकन आवेदन खारिज किया जाता है। राजस्व मण्डल का आदेश दिनांक 03-03-2014 यथावत रखा जाता है।


(अशोक शिवहरे)

सदस्य,
राजस्व मण्डल, म0प्र0